SOCIO-ECONOMIC RESEARCH INSIGHTS
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
समाजिक-आर्थिक अनुसंधान अंतदृष्टि
सामाजिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका

SERI 2026; 1(1): 03 Received: 15-01-2026 Accepted: 20-01-2026

महिला कल्याण में उज्जवला योजना की भूमिका

विभीषण कुमार
शोधार्थी
ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारी प्रबंधन
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय
भागलपुर– 812007 (बिहार)

परिचय

प्रधान मंत्री उज्जवला योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG), तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और राज्य सरकारों के सहयोग से किया गया था। लाभ लक्षित दर्शकों तक पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत पहचान और सत्यापन प्रक्रिया लागू की गई थी। पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों का उपयोग किया गया था, और इस योजना को देश के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था।

एलपीजी कनेक्शन को अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों पर प्रकाश डालते हुए व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए। इन अभियानों ने ग्रामीण महिलाओं को लक्षित किया, उन्हें पारंपरिक ईंधन के हानिकारक प्रभावों और एलपीजी पर स्विच करने के लाभों के बारे में शिक्षित किया। इस योजना को और अधिक लाभार्थियों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया, जिसमें एससी/एसटी समुदाय, वनवासी और चाय बागान श्रमिक शामिल हैं।

पीएमयूवाई के लिए पात्रता मानदंड

पीएमयूवाई योजना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए किसी भी आवेदक को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे

- आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा भारतीय नागरिक होनी चाहिए।
- वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होनी चाहिए तथा परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- परिवार की कुल मासिक आय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- आवेदक का नाम SECC–2011 सूची में होना चाहिए तथा तेल विपणन कम्पनियों द्वारा बनाए गए BPL डाटाबेस में दी गई जानकारी से मेल खाना चाहिए।

- आवेदक किसी अन्य समान सरकारी योजना में नामांकित नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आवेदक को कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे जो उसकी बीपीएल स्थिति, पहचान और अन्य प्रासंगिक जानकारी को सत्यापित करते हों।

भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं पर पीएमयूवाई का प्रभाव

Impact	2014-15	2023-2024	Growth rate
Total LPG sales	17,696 TMT	30,381 TMT	72%
Domestic LPG sales	16,041 TMT	26,208 TMT	63%
Domestic customers	14.52 crore	32.42 crore	123%
No- of bottling plants	186	210	13%
Bottling capacity	13,535 TMTPA	22,843 TMTPA	69%
Total distributors	13,896	25,481	83%
Distributors catering to rural areas	6,724	17,560	161%

स्रोत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, टीएमटी हजार मीट्रिक टन, टीएमटीपीए हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष

पीएमयूवाई सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रभावशाली योजना रही है, जिसका लाभ भारत में वंचितों को मिला है। यह पिछले एक दशक हुई प्रगति से स्पष्ट है। खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन स्रोतों की जगह एलपीजी का उपयोग करने के लक्ष्य के साथ, पीएमयूवाई योजना ने काफी प्रगति की है। भारत में कुल एलपीजी की बिक्री 2014–15 में 17,696 टीएमटी थी और अब यह 72% की वृद्धि दर के साथ 30,381 टीएमटी हो गई है। इसी तरह, घरेलू एलपीजी की बिक्री 2014–15 में 16,041 टीएमटी से 63% बढ़कर 2023–24 में 26,208 टीएमटी हो गई है। इसने स्वाभाविक रूप से एलपीजी कनेक्शन के लिए ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की है। घरेलू ग्राहक 2014–15 में 14.52 करोड़ से दोगुने से अधिक बढ़कर 2023–24 में 32.42 करोड़ हो गए हैं, जो 123% की वृद्धि दर दर्ज करता है।

एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन और वितरण की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। एलपीजी बॉटलिंग क्षमता 2014–15 में 13,535 टीएमटीपीए से बढ़कर 2023–24 में 22,843 टीएमटीपीए हो गई है, जो 69% की वृद्धि दर है। वितरण क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एलपीजी सिलेंडर के कुल वितरक 2014–15 में 13,896 से बढ़कर 2023–25 में 25,481 हो गए हैं, जो 83% की वृद्धि है।

पीएमयूवाई 2.0

10 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य PMUY के तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को एक करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन प्रदान करना है। इस पहल के तहत प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये (US$ 19.03) का बजटीय समर्थन दिया जाता है। वर्तमान पात्रता आवश्यकताओं के साथ, उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाते हैं:

- नए लॉन्च किए गए पोर्टल pmuy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन का विकल्प उपलब्ध है।
- पहला रिफिल और स्टोव निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

- प्रवासी अपने परिवार की संरचना की पुष्टि करने तथा पते का प्रमाण देने के लिए स्व–घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं।
- ई–केवाईसी आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके संचालित किया जाता है।

उज्ज्वला 2.0 के तहत अतिरिक्त एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य जनवरी 2022 में हासिल कर लिया गया था। इसके बाद उज्जवला 2.0 के तहत अतिरिक्त 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का फैसला किया गया। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने दिसंबर 2022 तक उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

लंबित आवेदनों और पीएमयूवाई कनेक्शनों की बढ़ती मांग के जवाब में, सरकार ने मौजूदा उज्जवला 2.0 दिशानिर्देशों के तहत अतिरिक्त 75 लाख जमा–मुक्त कनेक्शनों को अधिकृत करके योजना के विस्तार को मंजूरी दी। 2200 रुपये (यूएस$ 26.17) कनेक्शन के समर्थन के अलावा, योजना के तहत नए लाभार्थियों को मुफ्त पहला रिफिल और चूल्हा प्रदान किया गया।

पीएमयूवाई का भविष्य

चूंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का प्रबंधन करना जारी रखता है, इसलिए पीएमयूवाई का भविष्य सरकार की ऊपर उल्लिखित चुनौतियों का समाधान करने और अधिक परिवारों को कवर करने के लिए योजना का विस्तार करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। योजना की स्थिरता को बढ़ाने और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही पहल चल रही है।

- सामर्थ्य को बढ़ावा देना

बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी रिफिल को किफायती बनाने के लिए, सरकार कम आय वाले परिवारों के लिए लचीली भुगतान योजनाओं और लक्षित सब्सिडी की संभावना तलाश रही है। इन उपायों का उद्देश्य लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम करना और प्राथमिक खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करना है। सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 25 के दौरान पीएमयूवाई के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 300 रुपये (यूएस $3.57) प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से आनुपातिक) की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी। इस पहल के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल व्यय वित्त वर्ष 25 के लिए 12,000 करोड़ रुपये (यूएस $ 1.43 बिलियन) होगा।

- बुनियादी ढांचे का विस्तार

एलपीजी वितरण बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के प्रयास, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, आने वाले वर्षों में पीएमयूवाई की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सरकार मोबाइल एलपीजी वितरण इकाइयों और विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाओं जैसे अंतिम मील डिलीवरी के लिए समाधान विकसित करने के लिए ओएमसी और निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ काम कर रही है।

- अभियानों के माध्यम से जागरूकता फैलाना

एलपीजी अपनाने के प्रति सांस्कृतिक प्रतिरोध को संबोधित करने में व्यवहार परिवर्तन पहल महत्वपूर्ण है। सरकार, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों के साथ साझेदारी में, एलपीजी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय लाभों और पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

प्रौद्योगिकी PMUY पहल के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दे रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप लाभार्थी की पहचान को सरल बना रही हैं, कुशल सब्सिडी वितरण सुनिश्चित कर रहा हैं और LPG आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता हैं। इसके अलावा, डेटा एनालिटिक्स उपयोग के रुझानों की निगरानी कर सकता है और उन क्षेत्रों को इंगित कर सकता है जिन्हें आगे सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भारत के सबसे कमजोर नागरिकों को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा प्रदान करने की पहल की आधारशिला बन गई है। इनडोर वायु प्रदूषण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के जरिए, PMUY ने देश के ऊर्जा भविष्य को आकार देने में काफी प्रगति की है। हालाँकि, इसकी दीर्घकालिक सफलता सरकार की किफायतीपन. बुनियादी ढाँचे और सांस्कृतिक स्वीकृति से निपटने की क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे–जैसे भारत ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है और अपने जलवायु उद्देश्यों को पूरा करता है, PMUY सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है। निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता, नवोन्मेषी दृष्टिकोण और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ, PMUY में भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने और बेहतर भविष्य के लिए स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा पर निर्भर लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से पहले का जीवन

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आई क्रांति से पहले, करोड़ों परिवार लकड़ी, कोयला और गाय के गोबर के उपलों जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर खाना पकाने को मजबूर थे। धुएं वाली रसोई में खाना पकाना, दिन भर खांसना और सांस लेने में कठिनाई से जूझना भारतीय महिलाओं के लिए सामान्य बात थी। इससे न केवल उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता था, बल्कि पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी बढ़ती थीं। धुएं और हानिकारक कणों के बीच कई महिलाओं ने किसी अन्य विकल्प को पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। हालांकि, भारत सरकार ने मई 2016 में ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना पकाने के लिए एलपीजी जैसा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की। इस पहल ने पीढ़ियों से कठिनाइयों से जूझती आ रही भारतीय महिलाओं को मुक्तिदायक अनुभव प्रदान किया और अंततः धुआं–मुक्त रसोई का उनका सपना साकार हो गया।

महिला कल्याण पर प्रभाव

एलपीजी सिलेंडर के प्रावधान ने देश भर की महिलाओं को उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित किया है। कुछ महिलाएं पारंपरिक चूल्हों के अभिन्न अंग अस्वास्थ्यकर धुएं से मुक्ति पाने को लेकर आनंदित हैं, जबकि कुछ महिलाएं जलावन की लकड़ी बीनने में लगने वाले समय की बचत और इन प्रयासों से मिली राहत को महत्व देती हैं।

इस यात्रा के शुरूआती एक महीने के दौरान लगभग 3.77 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए नामांकन कराया है, जबकि 2016 में आरंभ की गई इस योजना के तहत करोड़ों महिलाएं पहले ही लाभान्वित हो रही हैं। यात्रा के दौरान अनेक महिलाओं द्वारा साझा किए गए अनुभवों पर यदि कोई गौर करे, तो वह बड़ी आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि पीएम उज्ज्वला योजना वास्तव में उल्लेखनीय रूप से बदलावकारी रही है, जो करोड़ों महिलाओं के जीवन को बेहतर बना रही है।

आइए सीमा कुमारी और बचन देवी के वक्तव्यों पर गौर करें –

बिहार के भागलपुर जिले की सीमा कुमारी को रोजाना रसोई में कठिनाइयों का सामना करना

पड़ता था । अनेक भारतीय परिवारों की तरह सुश्री सीमा कुमारी को भी खाना पकाने की पारंपरिक प्रथाओं का पालन करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें रोजाना जलावन की लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ती थी। धुएं के कारण वह सिरदर्द से परेशान रहती थीं और पारंपरिक खाना पकाने की प्रथाओं का पालन करने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जलावन की लकड़ी से खाना पकाने में काफी समय भी खर्च होता था । यह अथक दिनचर्या काफी मुश्किलों भरी थी, धुआं–मुक्त रसोई का विचार उनके लिए दूर के सपने जैसा था।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेप ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। एलपीजी सिलेंडर प्राप्त होते ही उनकी रसोई में व्यापक बदलाव आया और वह धुएं से मुक्त हो गई। अब वह अपने परिवार के लिए आसानी से भोजन तैयार कर सकती हैं। एलपीजी सिलेंडर के साथ, वह अब तेजी से भोजन पका सकती है, जिससे उनके समय की बचत हुई है और परेशानी से राहत मिली है। इस सुविधा ने बच्चों के लिए भोजन तैयार करना बहुत आसान बना दिया है। सीमा इस अमूल्य उपकार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बहुत आभारी हैं, क्योंकि इससे उनके जीवन बहुत बेहतर बना दिया है।

इसी तरह, बिहार के भागलपुर जिले की बचन देवी को भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनका समय जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने और जल्दी–जल्दी भोजन तैयार करने में व्यतीत हो रहा था, यह एक कठिनाई भरी दिनचर्या थी जो अंतहीन प्रतीत होती थी। जब सुश्री बचन देवी को लगा कि इन कठिनाइयों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो पीएम उज्ज्वला योजना ने उनके जीवन में अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव ला दिया। इस योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने से उनका जीवन बहुत बेहतर हो गया। सुश्री बचन देवी ने जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने के थकाऊ काम से निजात दिलाने वाले सिलेंडर के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया। इस नई सुविधा से वह बच्चों के लिए समय पर भोजन पकाने में समर्थ हो गई हैं, जिससे उनके कंधों से बड़ा बोझ उतर गया है।

संदर्भ ग्रंथ

1. भारत में महिला सशक्तिकरण की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और चुनौतियाँ, Rameshwari Pandya, New Century Publications, 2019
2. सामाजिक–आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी और नीतिगत विश्लेषण, Anuja Agrawal, New Century Publications,2020.
3. भारत में लैंगिक समानता पर आधारित रिपोर्ट, UNDP India 2021
4. ब्यूरो, पी.आई. (2016, 20 दिसंबर)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल महिलाओं को 1. 22 करोड़ से अधिक नए एलपीजी कनेक्शन जारी। नई दिल्ली, भारत ।
5. घरेलू वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तथ्य पत्रक छः 292 अपडेट किया गया। (2016, फरवरी) । तथ्य पत्रक अद्यतन किया गया।

6. घोष, एस.के. (2020)। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बाद उज्ज्वला योजना को ग्रामीण भारत का लाइववायर बनाना (अंक संख्या 73) । इकोरैप, एसबीआई ।
7. एम बंसल, आर. पी. सैनी, डी.के. खातोद, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के क्षेत्र का विकास– एक समीक्षा अक्षय और सतत ऊर्जा समीक्षा, खंड 17, पृष्ठ 44–53, पोस्ट किया गयाः 2013 ।
8. एस. अग्रवाल, एस. कुमार, एम.के. तिवारी – प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऊर्जा नीति के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली, खंड 118, पीपी। 455–461, 2018 ।
9. india-gov-in/spotlight/pradhan&mantri&ujjwala&yojana
10. www-petroleum-nic-in